2. Delhi School of Town and Country Planning.

3. Heavy Electrical Equipment Project.

4. Small Industries Service Institute (Temporary).

INTRODUCTION OF COST ACCOUNTING SYSTEM IN THE FILMS DIVISION

172. SHRI M. VALIULLA: Will the Minister for INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state whether the cost accounting system has been introduced in order to find out the cost of documentaries prepared by the Films Division?

THE MINISTER FOR INFORMATION AND BROADCASTING (DR. B. V. KESKAR): A cost accounting scheme has been sanctioned and will be put into operation shortly.

सीमेंट और लोहे का आवंटन

१७३. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को उतनी मात्रा में लोहा और सीमेंट नहीं मिल रहा है जितने की उसे आवश्यकता है ; और

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिये इन पदार्थों का कोटा निश्चित कर दिया है ?

†[ALLOCATION OF IRON AND CEMENT

173. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Government of Uttar Pradesh are not getting sufficient quantity of iron and cement for their requirements; and

(b) whether Government have fixed any quota of these materials for each State?]

वाणिज्य और उद्योग तथा **लोहा और इस्पात मंत्री** (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सीमेंट और इस्पात की उपलब्धि इन वस्तुओं की मांग से बहुत कम है । उपलब्ध माल सभी वर्गों के प्रयोगकर्त्ताओं को राशन के अनुसार दिया जाता है । चूंकि किसी भी राज्य की मांग पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाती है इसलिये अलग अलग राज्यों से शिकायत आ सकने की गुंजाइश तो है ही । प्रत्येक राज्य के लिये कोटे निर्धारित कर दिये गये हैं ।

†[THE MINISTER FOR COMMERCE AND INDUSTRY AND IRON AND STEEL (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): (a) and (b). Supplies of cement and steel are far below the demand for these commodities. The available supplies have to be rationed amongst all categories of users. Since the demand from any State is not fully met, there is room for complaint from individual States. The quotas are fixed for each State.]

कोरिया की समस्या

१७४. **श्रीमति सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तटस्थ राष्ट्र पर्यवेक्षण आयोग से यह प्रार्थना की थी कि कोरिया की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिये सम्बन्धित राष्ट्रों का एक सम्मेलन शीघ्र ही बुलाया जावे ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के कब तक बुलाये जाने की संभावना है ?

†English translation.